संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 29 दिसंबर, 2017 : पौष शुक्ल 11 वि. 2074

कर्म निराशा की दवा है

तीन तलाक पर कानून

सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक झटके में दिए जाने वाले तीन तलाक को अमान्य-असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भी इस तरह के मनमाने तलाक के मामले सामने आने के बाद उस पर कानून बनाना आवश्यक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आने से यही प्रकट हो रहा है कि तलाक की इस मनमानी प्रथा ने बहुत गहरे जड़ें जमा ली हैं। निःसंदेह तीन तलाक के मामले सामने आने की एक वजह यह भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरीखे संगठन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता शरीयत का गलत हवाला देकर करके अपने ही समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि अब उन्हें यह समझ आएगा कि वे समाज सुधार का रास्ता नहीं रोक सकते। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि किसी समाज का अपना ही धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व अपने लोगों को कुरीतियों से जकड़े रखने का काम करे? यह अच्छा हुआ कि तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। इससे भी अच्छा यह हुआ कि कांग्रेस ने इस विधेयक को समर्थन दिया। कांग्रेस ने इस विधेयक को समर्थन देकर एक तरह से 40 साल पुरानी अपनी भूल को सुधार लिया। अगर राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शाहबानो के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं होता तो शायद इस विधेयक की नौबत ही नहीं आती। अगर तब वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी गई होती तो शायद मुस्लिम समाज अब तक तीन तलाक की मनमानी प्रथा के साथ ही अन्य अनेक कुरीतियों से मुक्त हो गया होता।

निःसंदेह मनमाने तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने मात्र से यह सदियों पुरानी कुरीति समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि महिलाओं को असहाय बना देने वाली कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि सती प्रथा, दहेज की कुरीति और बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए गए। इन कानूनों ने इन प्रथाओं पर लगाम लगाने का काम किया तो इसलिए भी कि समय के साथ हिंदू समाज जागरूक हुआ। इसी जागरूकता की जरूरत तीन तलाक के चलन को खत्म करने के मामले में भी है। बेहतर हो कि इस मामले में राजनीतिक और साथ ही धार्मिक नेता सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे आएं। उन्हें मुस्लिम समाज की उन महिलाओं से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम मुसीबतों के बाद भी अपने हक की आवाज बुलंद की। इसी के साथ इस पर भी विचार होना चाहिए कि तीन तलाक के खिलाफ बनने जा रहा कानून कहीं आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं और वांछित नतीजे मिलेंगे या नहीं? ऐसा इसलिए, क्योंकि इस प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ जायज सवाल उठे हैं, जैसे यह कि यदि एक झटके में तीन तलाक देने वाला पति जेल भेज दिया जाएगा तो फिर पीड़ित महिला को राहत कैसे मिलेगी? बेहतर हो कि संसद की अंतिम मुहर लगने तक यह प्रस्तावित कानून ऐसे सवालों का समुचित जवाब देने में सक्षम हो जाए।

विधवा पेंशन की मुश्किलें

जिलों में बैठे कुछ अफसर राज्य सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भरण-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह चिंताजनक है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नौकरशाही की गिरफ्त में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। यह तो बात रही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पात्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते आखिरकार थक हार के बैठ गए।

> जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह चिंताजनक है

अफसरों की हीलाहवाली को देखते हुए सरकार ने इस योजना का लाभ पात्रों तक हर हाल में पहुंचाने को अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी ने कोई आवेदन पत्र निस्तारित नहीं किया तो वह अपने आप ही स्वीकृति के साथ उसके आगे के अफसर को अग्रसारित हो जाएंगे। ऐसे में यदि जनवरी तक आवेदन पत्र निस्तारित न हुए तो संबंधित महिलाओं की पेंशन अपने आप स्वीकृत हो जाएगी। हालांकि जिले के अफसर लाभार्थियों के स्थलीय निरीक्षण को भी जरूरी मानते हैं। सरकार की भी फर्जी लाभार्थियों पर अंकुश लगाने की मंशा है। अब देखना यह होगा कि ये कर्मचारी-अधिकारी सरकार की कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सेंसेक्स में आ रही तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती और भरोसे को दर्शाती है?

आज का सवाल

क्या तीन तलाक के खिलाफ कानून पर विपक्षी दलों की आपत्तियां वाजिब हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

साहसिक फैसलों पर जीत का साल

प्रशांत मिश्र

आम तौर पर सत्ताधारी दल चुनावी मौसम में कमजोर हो जाता है, लेकिन मोदी ने सबसे अहम चुनावों से पहले ही सबसे ज्यादा जोखिम लिया

राजनीति में बदलाव हमेशा से तेज ही होता है पर समाज भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े और राजनीति के केंद्र में समाज आने लगे तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व अहम है। वरना कोई कारण नहीं है कि नरेंद्र मोदी विपरीत हवा में भी खड़े होकर उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। यह भी सच्चाई है कि हाल के वर्षों में विकास और सामाजिक जागरूकता भी मुद्दा बना है। जातिवाद खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन विकासवाद उस पर हावी होता जरूर दिखा है और यह आशा बंधी है कि राजनीति अब समाज केंद्रित होगी। घटनाओं से भरा साल 2017 खत्म होने को है। ऐसे में राजनीति की विवेचना की जाए तो केवल चुनावी जीत-हार तक सीमित रहना सही नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि नतीजे के लिए जिम्मेदार जनता किस तरह सोचती है। इस कसौटी पर उत्तर प्रदेश से लेकर हाल के गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक यह स्थापित हो गया है कि चुनाव में भी विकास बिकाऊ मुद्दा है। इसे इसलिए बदलाव माना जाएगा, क्योंकि अब तक यही माना जाता रहा है कि विकास चुनाव नहीं जिताता है। वरना अटल बिहारी वाजपेयी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं हारते। अब स्थिति बदल गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। विकास की चाहत ने भाजपा को ऐसी उंचाई पर खड़ा कर दिया जहां से दूसरे सभी दल ठिगने दिखने लगे। पड़ोस के उत्तराखंड में बदलाव की ऐसी बयार बही कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री दो सीटों से लड़ने के बावजूद नहीं संभल पाए। इसी तरह पंजाब में अकाली सरकार बह गई और विकल्प के रूप में सामने खड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से जनता ने कांग्रेस को भारी मत से चुना। पंजाब की जनता ने ऐसा चेहरा चुना जो विश्वसनीय था। जनता को ऐसा चेहरा पसंद नहीं आया जो संवेदना भड़काकर वोट की आस देख रहा था। बहुत मुश्किल से विकास और शांति की राह पर बढ़े पंजाब के लोगों ने फिर से उस आग की ओर बढ़ने से इन्कार कर दिया।

2016 के अंत में नोटबंदी का साहसिक फैसला हुआ था। साहसिक इसलिए, क्योंकि चार महीने बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था। विपक्ष को मानों घर बैठे मुद्दा मिल गया और उसने नए नोट के लिए लाइन में लगने वाले कुछ लोगों की मौत को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आम जनता ने काले धन की सफाई के अभियान पर मुहर लगा दी। इसमें कोई शक नहीं कि नोटबंदी के बाद कई गरीब परिवारों के लिए भी तात्कालिक रूप से संकट पैदा हो गया था, लेकिन उन्होंने भी समाज और देश में बदलाव के लिए सरकार के फैसले के साथ अपना हाथ जोड़ दिया था। कुछ ही दिन बीते कि मोदी सरकार ने जीएसटी को भी अमल में लाने की घोषणा कर दी। एक तरह से सात-आठ महीने के अंतराल में दो बड़े साहसिक कदम राजनीतिक बदलाव को दिखाते हैं। सामान्यतया सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल और नेतृत्व चुनावी मौसम में कमजोर हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अहम चुनावों से पहले ही सबसे ज्यादा जोखिम लिया। जब उत्तर प्रदेश और गुजरात दांव पर था तभी उन्होंने सबसे बड़े फैसले किए। ऐसे फैसले जिसने कईयों के पैर उखाड़ दिए, लेकिन देश को ताकत दे दी। शायद यह आत्मविश्वास का असर हो या फिर इसका कि वह गुजरात के पुराने अनुभव से प्रेरित रहे हों। गुजरात में 12 साल तक सत्ता में रहे मोदी का रिकार्ड रहा है कि वह चुनावों से पहले भी सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकते थे। ध्यान रहे कि ब्रांड मोदी का निर्माण वहीं हुआ था। गुजरात का चुनाव ऐसे हुआ जैसे लोकसभा चुनाव हो रहा हो। विपक्ष ने जीएसटी को खूब जोर-शोर से मुद्दा बनाया, समाज के प्रभावी पटेल वर्ग को साधने के लिए आरक्षण का भी दांव चला। उस विकास को पागल भी करार दिया जिससे गुजरात की पहचान होने लगी है। ये सभी मुद्दे फिस्स साबित हुए और फिर से भाजपा ही सत्ता में आ गई।

अवधेश राजपूत

हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल की हार के बावजूद भाजपा को भारी बहुमत का भी एक अर्थ है और वह यह कि जनता के लिए व्यक्ति नहीं वह पार्टी महत्वपूर्ण हो गई है जो विकास कर सकती है। स्थानीय नेतृत्व किसके हाथ में होगा, यह गौण हो गया और हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विश्वास कर लिया। सवाल उठता है कि आखिर किसी पर इतना भरोसा कैसे पैदा हो सकता है कि जनता किसी पार्टी को तीन साढ़े तीन साल में देश का लगभग सत्तर फीसद हिस्सा सौंप दे? भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी आयरन लेडी मानी जाती रही हैं। जवाहर लाल नेहरू तो चाचा नेहरू ही बन गए थे, लेकिन उनके वक्त में कांग्रेस का इतनी तेजी से विकास नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रबंधन ने साढ़े तीन साल में ऐसा करिश्मा किया कि भाजपा और राजग की सरकारें 19 राज्यों में स्थापित हो गईं। सही मायने में नरेंद्र मोदी ने अब तक के सभी मापदंड तोड़ दिए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनकी सोच-समझ छोटे से कसबे तक भी पहुंचती है। जनता से संवाद स्थापित करने में जितने मोदी सफल रहे हैं वह इंदिरा और नेहरू के लिए भी संभव नहीं हो सका था।

अगर बीतते साल की बात करें तो सात राज्यों में चुनाव हुए और छह में भाजपा की सरकार बनी। विपक्ष की ओर से ईवीएम जैसे मुद्दे भी उछाले गए, लेकिन हाल के चुनाव में खुद ईवीएम ने यह साबित कर दिया कि वह पास है। अब भविष्य पर नजरें टिकी हैं। डेढ़ साल बाद लोकसभा चुनाव है। उससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ-साथ उत्तर पूर्व के चार राज्यों में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा, केरल के अलावा वामपंथ का आखिरी गढ़ बचा है। भाजपा का वहां जिस गति से विकास हुआ है उसे देखते हुए त्रिपुरा में भी केसरिया लहराए तो हैरत नहीं। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जिस तरह अपना वोट शेयर बढ़ाया है और कांग्रेस जनाधार खो रही है उसकी झलक त्रिपुरा में भी दिखी है। वहां तृणमूल के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दक्षिण में कर्नाटक की जीत भाजपा के लिए सुदूर दक्षिण में भी विस्तार का रास्ता खोलेगी। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे सत्ताविरोधी लहर से जूझना पड़ सकता है। राजस्थान में तो खेमेबाजी शुरू से भाजपा के लिए सिरदर्द का कारण रही है। इन राज्यों में भी भाजपा की जीत हुई तो फिर कभी कोई विकास को पागल करार देने की जुर्रत नहीं करेगा।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)

response@jagran.com

बेशर्मी पर आमादा पाकिस्तान

विवेक काटजू

जाधव परिवार की महिलाओं से अशिष्ट आचरण दर्शाता है कि पाक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को कमजोर नहीं पड़ने देगा

पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव से मिलने गईं उनकी मां अवंति और पत्नी चेतना के साथ वहां जैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ उस पर देश भर में फैला आक्रोश पूरी तरह जायज है। क्रिसमस के जिस दिन यह मुलाकात हुई उसी दिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन भी होता है। पाकिस्तान ने कहा कि उसने जानबूझकर यह दिन चुना ताकि जिन्ना की याद में अपने मानवीय पहलू और इस्लामी तालीम को दिखा सके, लेकिन उसने दोनों भारतीय महिलाओं के साथ जैसा शर्मनाक व्यवहार किया उससे उसकी छवि और मलिन ही हुई है। उसके अशिष्ट आचरण पर हैरानी इसलिए नहीं, क्योंकि उसका इतिहास ऐसी ही अनगिनत मिसालों से भरा पड़ा है जब उसने गैर-इस्लामी समूहों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं का अनादर कर उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाई है। इसकी सफाई वही दे सकता है कि अवंति और चेतना जाधव को मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियां उतारने के लिए क्यों कहा गया? क्या पाकिस्तानी अधिकारियों को नहीं पता कि हिंदू विवाहित महिला के लिए ये साधारण आभूषण नहीं, बल्कि उनके सुहाग की निशानियां होती हैं और कोई उनसे उन्हें उतारने के लिए नहीं कह सकता। यदि सुरक्षा कारणों से उतारने के लिए कहा भी जाए तो तुरंत उन्हें वापस करना होता है। फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ?

पाकिस्तानी प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन महिलाओं का सामान उनके विदेश मंत्रालय छोड़ने से पहले ही लौटा दिया गया था। क्या इनकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था में कोई अवरोध आ रहा था जो उन्हें इतनी देर तक रखा गया? कोई इसकी कल्पना ही कर सकता है कि जब अवंति और चेतना बिना मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियों के कुलभूषण जाधव से मिली होंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? इस करतूत के लिए पाकिस्तान को दोनों भारतीय महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने तमाम परंपराओं को ताक पर रख दिया। उसने मीडिया को दोनों महिलाओं के पास फटकने की इजाजत दी और मीडिया के लोगों ने भी उनसे अपमानजनक सवाल किए। कोई भी सभ्य सरकार इस तरह के असभ्य और अशिष्ट व्यवहार की इजाजत नहीं दे सकती। पाकिस्तान ने इस मुलाकात की फोटो भी जारी कीं। क्या कैद में रखे गए शख्स की उसके परिजनों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से जारी की जानी चाहिए? पाकिस्तान ने ऐसा करके दुनिया को अपना असंवेदनशील चेहरा ही दिखाया। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जाधव की मां और पत्नी के साथ कोई भारतीय महिला राजनयिक रहे, क्योंकि इससे वह पूरे समय उनके साथ रहती। पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को भी बातचीत नहीं सुनने दी जबकि पाकिस्तानी उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। कोई भी देश किसी मां को अपने बेटे के साथ मातृभाषा में बात करने से नहीं रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा ही किया।

पाकिस्तान का शर्मनाक आचरण कोई नया नहीं है। वह अक्सर ऐसा ही करता आया है और इसकी पुष्टि उसके साथ संपर्क में आया कोई भी भारतीय राजनयिक कर सकता है। जाधव परिवार की महिलाओं ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को यह भी बताया होगा कि कुलभूषण ने उन्हें क्या बताया? ऐसे मामलों में कई बातें स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक दायरे में नहीं आतीं। हालांकि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह बात सामने आ रही है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानियों ने खूब प्रताड़ित किया है और उसे ऐसी बातें बोलने के लिए मजबूर किया जिनसे पाकिस्तान की अच्छी छवि बने। जाधव की शारीरिक हालत के बारे में ठीक से कुछ नहीं पता। जिन परिस्थितियों में जर्मन डॉक्टर का प्रमाण पत्र लिया गया उनके बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं और इस कारण उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वह अंतरराष्ट्रीय समझौते और नैतिकता का भी उल्लंघन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम को वह किसी तरह कमजोर नहीं पड़ने देगा। वह पूरी तरह से प्रोपेगैंडा में लगा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा मुलाकात के बाद जाधव का जारी किया हुआ वह वीडियो इसकी मिसाल है जिसमें अपनी मां और पत्नी से मुलाकात की इजाजत देने के लिए जाधव ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। यह पाकिस्तान के प्रचार तंत्र का ही हिस्सा है। चूंकि जाधव को पूरी तरह फर्जी मामले में मौत की सजा सुनाई गई है इसलिए उनकी मानसिक और भावनात्मक व्यथा समझी जा सकती है। पाकिस्तान द्वारा काउंसलर एक्सेस की इजाजत न देने से भी उनके तनाव और अकेलेपन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यह और स्पष्ट है कि पाकिस्तान का केवल यही मकसद था कि वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह बता सके कि वह उन लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी कितनी दया के साथ पेश आता है जो उसके देश में कथित तौर पर जासूसी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। हालांकि जैसे वह जाधव पर लगे झूठे आरोपों को लेकर दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाया उसी तरह जाधव परिवार की महिलाओं के साथ अशिष्ट व्यवहार के बाद उसका यह दांव भी बेकार ही जाने वाला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों के साथ हुए दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करके एकदम सही किया। पाकिस्तान जिस निचले स्तर पर उतर सकता है उसकी तो अधिकांश भारतीय आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते। चेतना जाधव के जूते जब्त करने की हरकत भी पाकिस्तान की पोल खोलती है। संभवतः इससे भारत में उस तबके की आंखें भी खुलेंगी जो पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों के बावजूद उसके साथ बेहतर रिश्तों की हिमायत करता है।

जाधव प्रकरण पाकिस्तान द्वारा रचा गया ऐसा प्रपंच है जिसके जरिये वह यह साबित करना चाहता है कि भारत पाकिस्तान में आतंक को बढ़ावा देता है। जाधव के खिलाफ आधारहीन आरोपों के साथ ही उसने अन्य अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि वे भी जाधव के साथ षड्यंत्र में शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान किसी भी देश को समझाने में नाकाम रहा है, फिर भी वह लगातार कोशिश में लगा है और जाधव के परिवार से मुलाकात के मौके को भी उसने जाधव के खिलाफ आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित कराने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत द्वारा जाधव तक काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने की अर्जी पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। वहां भारत के पक्ष में आने वाला फैसला इस मामले में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब ही करेगा।

(विदेश मंत्रालय में सचिव रहे लेखक पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मनुष्य की तलाश

मनुष्य की तलाश, यह स्वर अक्सर सुनने को मिलता है। यह भी सुनने को मिलता है कि आज आदमी आदमी नहीं रहा। दार्शनिक खलील जिब्रान का कथन है कि ईश्वर का पहला चिंतन था-फरिश्ता और ईश्वर का ही पहला शब्द था मनुष्य। ईश्वर के प्रारंभिक दोनों ही चिंतन आज लुप्तप्राय हैं। इन्हीं स्थितियों के बीच दार्शनिक डॉ. राधाकृष्णन की इन पंक्तियों का स्मरण हो आया, 'हमने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया है, किंतु मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा है।' दार्शनिक गेटे की प्रसिद्ध उक्ति है कि जब कोई आदमी ठीक काम करता है तो उसे पता तक नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, पर गलत काम करते समय उसे हर क्षण यह ख्याल रहता है कि वह जो कर रहा है, वह गलत है। गलत को गलत मानते हुए भी इंसान गलत कार्य किए जा रहा है। इसी कारण समस्याओं और अंधेरों के अंबार लगे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद उनकी अच्छाइयों के कारण ही जीवन बचा हुआ है। ऐसी अनेक जिंदगियों को मैंने नजदीक से देखा है। वे सारे फरिश्ते थे, ऐसा मैं नहीं मानता। वे आदमी थे, केवल आदमी। आदमी की सारी अच्छाइयां और कमियां उनमें भी थी। फिर भी मुझे उनमें आदमियत नजर आई।

कबीर, दादू, रैदास, आचार्य तुलसी, वल्लभ गुरु आदि को तो पढ़ाई-लिखाई का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन संतुलित जीवन और विचारों की साधना ने उन्हें ज्ञानी बनाया और उन लोगों ने जीवन भर उस ज्ञान को लोगों में बांटा। विचारों का असंतुलित प्रवाह नुकसानदेह है, जो इस पर अनुशासन करना सीख लेता है, उसके लिए यह वरदान है और जो इसके वशीभूत होकर अपनी विवेक चेतना खो देता है, वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। जीवन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ वस्तु से कुछ भी कम स्वीकार करने से इन्कार करते हैं तो अक्सर आप उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा कि हमें वह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। जरूरत है हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी वातायनों और खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा इंसान को इंसान नहीं रहने देती।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

पहले पलायन रोके यूपी सरकार

दिखने लगी बदलाव की नई बयार शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की विकास की कुछ नीतियों का उल्लेख किया। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी, और दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों तो बदलाव की नई बयार तो दिखेगी ही, लेकिन प्रदेश में नई बयार तो सचमुच तब मानी जाएगी, जब दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने वाले लोग घर वापसी करने लगेंगे। जबसे यूपी में योग सरकार आई है, तबसे राज्य की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। तभी तो कुछ उद्योगपति प्रदेश में निवेश करने का मन बना रहे हैं। अगर योगी सरकार यूपी में उद्योग का विस्तार और कृषि में सुधार करने में कामयाब हो जाती है तो इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य की आय बढ़ेगी और 2019 के आम चुनाव में भाजपा का वोट बैंक भी बढ़ेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाक मांगे माफी

पाक ने कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ ठीक नहीं किया। उसने हिंदू रीति-रिवाज का भी अपमान किया है। साथ ही उसने ऐसा करके भारत को भी उकसाने की कोशिश की है। इस तरह उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उसे ऐसी तुच्छ हरकत के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। कोई भी देश इस तरह किसी भी तरह की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से खिलवाड़ नही करता है और ना ही इसकी इजाजत किसी को देता है। हमारी सरकार को पाक द्वारा कुलभूषण की मां और पत्नी को जलील करने के मामले में उससे माफी मंगवाना चाहिए और मामले को संयुक्तराष्ट्र संघ में उठाना चाहिए, ताकि फिर कभी पाक हमसे गलत हरकत करने की गुस्ताखी न कर सके। mahesh_nenava@yahoo.com

घिनौनी सोच

कुलभूषण जाधव से मिलने गईं उनकी मां व पत्नी का जिस तरह से पाकिस्तान ने अपमान किया वह भारतीय महिलाओं के प्रति पाकिस्तान की घिनौनी सोच को दर्शाता है। पाक ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के मंगल सूत्र, चूड़ियां और बिंदी भी उतरवा ली। पाक का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सब किया गया। जब इन्हें भारत की महिलाओं की बिंदी से भी खतरा है तो इन्हें हथियार डाल देने चाहिए। पाकिस्तान शायद यह बात भूल रहा है कि जब हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था तब इन्हीं महिलाओं ने भी रानी लक्ष्मीबाई बनकर देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नारी के स्वाभिमान के प्रतिक चिह्नों के साथ छेड़छाड़ करने का अंदाजा शायद इन्हें पता नहीं कि इसका क्या हश्र हो सकता है। 97295108|ys@gmail.com

निंदनीय कार्य

पाकिस्तान में कुलभूषण जाघव के परिवार से जो सलूक किया गया उससे बेहतर की उम्मीद शायद ही कोई भारतवंशी कर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी और मां के साथ वहां सलूक हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। वहां के प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उनकी पत्नी के सुरक्षा के नाम पर जूते निकलवाए गए व बाद में उस पर चिप मौजूद होने का दावा करते हुए जासूसी जैसा घिनौना आरोप लगाया गया वो अकल्पनीय था और उससे भी बढ़कर पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह से मखौल उड़ाया वो निंदनीय है। एक बार फिर भारत असहज महसूस कर रहा है उस परिवार के सामने जिसके बेटे को पाकिस्तान ने मौत की सजा का एलान कर रखा है। इस मुद्दे पर विश्व समुदाय और भारत को राजनीति से परे होकर दूरगामी कड़े फैसले लेने होंगे। ss6066356@gmail.com

भरोसे के काबिल नहीं पाक

पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव की मां व पत्नी का अपमान करना पाकिस्तान की मध्ययुगीन मानसिकता का परिचायक है। सोचिए उस बेटे पर क्या गुजरी होगी जिसके सामने सुहागिन होते हुए भी उसकी मां व पत्नी को विधवा के रूप में लाया गया होगा। पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी के जूते भी साजिश के तहत ही रखे हैं, ताकि उनमें कोई आपत्तिजनक चीज मिलने का आरोप मढ़ सके। पाकिस्तान कतई भी भरोसे के काबिल नहीं है, वह किसी भी हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान का जन्म ही भारत से शत्रुता की कोख से हुआ था। आरंभ में ही पाकिस्तान ने कबाइलों के भेष में अपनी सेना भेजकर कश्मीर को हड़पने का कुत्सित प्रयास किया। कुंठित पाकिस्तान ने भारत से कई युद्ध लड़े पर हर बार मात खाई । भारत ने हर बार सदाशयता का परिचय दिया और उसके जीते हुए इलाके वापस लौटा दिए। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने हथियार डाल कर समर्पण करने वाले पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों को भारत ने सकुशल पाकिस्तान को वापस लौटा दिया था, जबकि आज भी भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान ने पकड़े गए हमारे सैनिकों के शव क्षत-विक्षत कर सिर काट कर ले जाने जैसे घृणित कार्य किए हैं। ऐसे विषम हालात के बावजूद भी भारत ने संबंध सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। साल 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन की आस में बस लेकर लाहौर गए थे। बदले में हमें कारगिल का युद्ध मिला। वाजपेयी ने मुशर्रफ को वार्ता के लिए आगरा बुलाया तो भारत को अपनी संसद पर हमला झेलना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी भी अफगानिस्तान से वापस आते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज से मिलने जा पहुंचे थे, किंतु भारत के सभी सद प्रयास विफल रहे। पाकिस्तान से किसी भी सदभाव की अपेक्षा करना व्यर्थ है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

ट्वीट-ट्वीट

तीन तलाक में जेल जाने वाले के बीवी-बच्चों का क्या होगा? सलमान खुर्शीद की यह दलील तो देश की जेलों में बंद तमाम हत्यारों और दुष्कर्मियों के लिए भी मददगार होगी। फिर यही कहा जाएगा कि अगर आप ऐसे अपराधियों को जेल में डाल देंगे तो उनके परिवारों को कौन संभालेगा?
सुनील जैन@thesuniljain

मांओं-बहनों-भाभियों-बेटियों के हक में बन रहे एक सार्थक कानून का स्वागत है। आशा है पक्ष-विपक्ष इसे अपने-अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण का हथियार बनाने की अपेक्षा आधी आबादी की बेहतरी की दृष्टि से समझेंगे।
कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

भारत को पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने की कपोल कल्पना से बाहर आना चाहिए। महज बयानबाजी के बजाय इस दुष्ट देश को आतंकी घोषित किया जाए और नापाक हरकतों के लिए जवाबदेह बनाएं। मेरी सलाह है कि इस बिगड़ैल पड़ोसी के बारे में बोलिए कम और करिए ज्यादा।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

मैं यह नहीं बता सकता कि आधार पर संसदीय पैनल की बैठक में क्या हुआ, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वंचित लोगों पर आधार थोपने का तृणमूल हरसंभव विरोध करेगी।
डेरेक ओ ब्रायन@derekobrienmp

जनपथ

जूता चोरी कर लिया दिखलाई औकात,
फिर बयान वह दे रहा 'है छोटी सी बात'।
है छोटी सी बात और दिल भी है छोटा,
है छोटा सा देश मगर है बहुतै खोटा।
चले तोप-बंदूक न इतना उसका बूता,
मट्ठे में भिगवाय चलाओ उस पर जूता।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 164